



भारत में सेंसरशिप प्रणाली

प्रलिस के लयः

केंद्रीय फललड डुरड (Central Board of Film Certification), डारतीय दंड संहतल (IPC)

डेनुस के लयः

डारत डें सेंसरशलड डुरणाली एवं वरुतडान डें इससे संबधतल डुरावधान, सरकारी नीतयलँ और हसुतकषेड, नीतयलँ के डुऑलडन और कारुडानवडन से उतुडनुन डुदुडे

सेंसरशलड का तातुडुरडुः

- सेंसरशलड एक ऐसा डाधुडड है ऑ डुस डारत की नषुडकष ऑऑ करतल है कसलरुवऑनकल डुडेडन डें कडु डुरसारतल कडुडल ऑलनल ऑलहडल। सलथ ही डुह ऑलनकारी अथवल डुडुडल शलंतल, सदुडलव एवं सलडलऑकल वुडवसुथल डुनलए ररखने के लडु कडुऑ सलडलनुड रूड से सुवीकारुड डलनकुँ कुँ से डुरल करतल है?
- डारतीय कलनुन डें 'सेंसरशलड' शडुद ने अकसुर आड लुगुँ, रलऑनेतलऑँ, वऑलरकुँ, संगठनुँ और वडुडलनुन अनुड सडुडुँ के डुलऑ ऑुरदलर डुहस कुँ ऑनुड दडुडल है।
- हललुँकल, सेंसरशलड के अरुथ, संचललन के आधलर एवं वुडलखुडल के कडुँ ऐसे आडलड है ऑ डुस आडतुँर डुर डुरहण की गडुँ डुरडलषल से डुरे है और इसके आवेदुन और अवलुकन की डुरकरुडल डें वुडकुतुनलषलठ है। इससे सेंसरशलड कलनुन कल दुरुडुडुऑ हुने कल खतरल डुनल रहतल है।
- डारत के संदरुड डें सेंसरशलड कलनुन सलरुवऑनकल डुडेडन डें आने वलले डुरतुडेक वषलड कुँ अडुने डुरडलवकषेतर डें लेते है - वऑऑलडन, थरुडर, फललडें, शरुखलल, संगलत, डलषण, रडुडुररुड, डुहस, डुतरकललएँ, सडलऑलर डुतर, नलडक, कलल, नृतुड, सलहलतुड, लखलतल, वृतुतऑतलर डल डुलखकल करुडुँ के कुँ डुल रूड।
- इस डुरकरुडल ऐसे कडुँ उदलहरण है ऑड डलषणुँ और सलरुवऑनकल अडुवलडकुतुल के अनुड रूडुँ कुँ अडुडलनऑनक, अडुदर, अनैतकल एवं सलरुवऑनकल वुडवसुथल के खलललड डल धलरुडकल डुडलनलऑँ कुँ आहत करने के करलण सलरुवऑनकल डुडेडन से हडल दडुडल गडुडल है। वसुतुतः डे ऐसे डुरलडुडर ऑनकल कुँ डुल वशलषलठ डुरडलषल डल उऑतल रूडुरेखल तड नही है।
- ऐसे उदलहरण उनकल डुहतुवलकलकषल, दलडरे और सखुडल डें डुद रहे है एवं डलषण और अडुवलडकुतुल की सुवतंतुरतल के लडु एक डुडे खतरे के रूड डें देखे ऑलते है।

डारत डें करुड डुरणालीः

- सेंसरशलड डुरकरुडल संबधतल डुरलधकलरल डल नलडतल नकलड दवलरल की ऑलतल है।
- सेंसरशलड कल डुरडुऑ डारत डें डुरतुडकष और अडुरतुडकष रूड से वडुडलनुन कलनुनुँ और डुरलधकलरणुँ के डलधुडड से डुथलडारतीय दंड संहतल, दंड डुरकरुडल संहतल, केंदुरल डललड डुरडलन डुरड, डारतीय डुरेस डुरलषलद, सनलडुडुऑगुरलड अधनलडडड, 1952, केडल डेलीवऑन अधनलडडड आदल ऑसे वडुडलनुन डुडेडन डें कडुडल ऑलतल है।

डारत डें सेंसरशलड कुँसे करुड करतल है?

- दंड डुरकरुडल संहतल (CrPC):
 - CrPC की धलरल 95 कुँऑ सलडगुरल/डुरकलशनुँ कुँ ऑडत करने की अनुडतल देतल है।
 - इस धलरल के तहत डुदल कसलल सडलऑलर डुतर, डुरसुतक डल दसुतलवेऑ डल ऑहलँ डुल डुदरुतल हुते है, डें कुँ डुल ऐसल डलडलल है ऑसे रलऑुड सरकलर, रलऑुड के लडु हलनकलरक डलनतल है तुल वुह एक आधकलरकल अधसुलऑनल के डलधुडड से रलऑुड सरकलर दवलरल दंडनीड हुगल।
 - इसके तहत डलऑसलदुरेड 'आडतुतऑनक' डुरकलशनुँ की तललशी के लडु वलरुंत ऑलरल करने की अनुडतल दे सकतल है।
- केंदुरल डललड डुरडलन डुडुरु (CBFC):
 - केंदुरल डललड डुरडलन डुडुरु (CBFC) सनलडुडुऑगुरलड अधनलडडड, 1952 के तहत संचललतल एक वुधलनकल नकलड है।
 - डुह सलरुवऑनकल डुडेडन डें ललई ऑलने वललल डललडुँ की सलडगुरल कुँ नडुतुरतल करतल है।
 - CBFC डललडुँ के डुरव डुरडलन की डुरणाली कल डललन करतल है। डुरसरक डुरदतुत डुरडलन कल डललन करने के लडु 'करुडकरुड' है।

संहिता और वजिजापन संहिता' के तहत दशानरिदेशों से बंधे होते हैं।

○ वर्तमान में फलिमों को 4 श्रेणियों के तहत प्रमाणित किया जाता है: U, U/A, A & S।

● अप्रतबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी (U)।

● अप्रतबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी लेकिन सावधानी के साथ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये माता-पिता के वविक की आवश्यकता (U/A)।

● अवयस्कों के लिये प्रतबंधित (A)।

● व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिये प्रतबंधित (S)।

■ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया:

○ यह एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित किया गया था।

○ यह प्रेस के लिये स्व-नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है और मीडिया डोमेन में आने वाली चीजों को नियंत्रित करता है।

○ यह निकाय मीडियाकर्मियों और पत्रकारों द्वारा आत्म-वनिियमन की आवश्यकता पर जोर देता है, और बड़े पैमाने पर मीडिया सामग्री के लिये एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या यह प्रेस नैतिकता और सार्वजनिक हित के खिलाफ है।

■ केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम:

○ यह अधिनियम वैसी सामग्री को भी फिल्टर करता है जिसे प्रसारित किया जा सकता है।

○ केबल ऑपरेटरों पर नजर रखने के लिये अधिनियम केबल ऑपरेटरों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

○ यह केबल ऑपरेटर द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री को वनिियमति करने के लिये प्रावधान भी करता है। केबल टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण के पूरे यह CBFC द्वारा श्रेणी- U (यानी अप्रतबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी) के तहत फलिम के प्रमाणन को अनिवार्य करता है, भले ही फलिम भारत में नरिमति हो या वदिश में।

○ यह अधिनियम सरकार को केबल ऑपरेटरों, चैनलों या कुछ कार्यक्रमों पर प्रतबंध लगाने के लिये पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है जो 'केबल टेलीविजन नेटवर्क नयिम' अधिनियम के तहत बनाए गए नयिमों द्वारा नरिधारित कार्यक्रम कोड या दशानरिदेशों का उल्लंघन करते हैं।

■ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नए IT नयिम, 2021:

○ सोशल मीडिया की वृद्धिदर को देखते हुए, इसकी सेंसरशिप भारत में चिता का वषिय रहा है क्योंकि हाल के दिनों तक, यह किसी भी सरकारी प्राधिकरण और वशिषिट वनिियमन की प्रत्यक्ष देखरेख में नहीं था।

○ वर्तमान में, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सोशल मीडिया के उपयोग को वनिियमति करता है एवं वशिष रूप से धारा 67A, 67B, 67C और 69A में वशिषिट नयिमक खंड शामिल हैं।

■ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशान-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) नयिम, 2021:

○ इन्हें IT अधिनियम, 2000 के तहत 'एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स' में संशोधन कर लाया गया था, ताकि फलिमों, ऑडियो-वज्जुअल कार्यक्रमों, समाचार, समसामयिक मामलों की सामग्री और अमेज्जोन, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफार्मों सहित डजिटल और ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के दायरे में लाया जा सके।

○ इस संशोधन के बाद लागू IT (मध्यवर्ती दशानरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) नयिम, 2021 में सोशल मीडिया, OTT, डजिटल समाचार और यहाँ तक कि मैसेजिंग ऐप (जैसे व्हाट्सएप और वाइबर) के लिये नए अनुपालन और नवारण तंत्र शामिल हैं।

सेंसरशिप के पक्ष और वपिक्ष में तर्क:

■ पक्ष:

○ वैमनस्य की रोकथाम:

● सेंसरशिप आपत्तजनिक सामग्री के प्रकटीकरण की रोकथाम करके समाज में वैमनस्य को रोकता है जो सांप्रदायिक कलह का कारण बन सकता है

○ राज्य की सुरक्षा देखभाल:

● इंटरनेट की सेंसरशिप सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में मदद कर सकती है।

● चूँकि इंटरनेट सेंसरशिप बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियों और इंटरनेट अपराधों को रोकने में मदद कर सकती है, इसलिये यह समाज की स्थिरता के लिये अच्छा है।

● कुछ अवैध संगठन या लोग गलत जानकारी जारी कर सकते हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिको नुकसान पहुँचा सकता है।

● आतंकवादी और चरमपंथी तथ्यों को वकित करने के लिये झूठी जानकारी जारी कर सकते हैं, जनता को भ्रमति कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से भय और आतंक पैदा कर सकते हैं।

○ समाज में नैतिकता का अनुरक्षण:

● सेंसरशिप समाज में नैतिकता बनाए रखने में मदद कर सकती है।

○ झूठी मान्यताओं या अफवाहों के प्रसार पर प्रतबंध:

● सरकार झूठी मान्यताओं या अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिये सेंसरशिप का उपयोग कर सकती है और साथ ही उनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाकर अन्य लोगों की हानिकारक गतिविधियों तक पहुँच को प्रतबंधित कर सकती है।

● इंटरनेट की सेंसरशिप अनुचित जानकारी को ऑनलाइन फिल्टर कर सकती है और बच्चों को परेशान करने वाली वेबसाइटों यथा बाल पोर्नोग्राफी, यौन हसिा और अपराध या नशीली दवाओं के उपयोग में वसितुत नरिदेश से बचा सकती है।

■ वपिक्ष:

○ नैतिक पुलसिगि के लिये उपकरण:

● सेंसरशिप कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग नैतिक पुलसिगि का एक उपकरण बन सकता है जो बड़े सार्वजनिक मुद्दों के साथ खुद को संबधित करने के बजाय अन्य लोगों के जीवन को नियंत्रित करता है।

- नए नियमों के तहत **नियामक निकाय को दी गई व्यापक शक्तियाँ**, जो नौकरशाहों के अधीन हैं, वविकाधीन राजनीतिक नियंत्रण का जोखिम भी उठाती हैं।
- **अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के संवैधानिक जनादेश के खिलाफ:**
 - नैतिकता, रूचि और अरुचि की परिधि में भारत में व्यापक भ्रमिता है।
 - इसलिये, गहन सेंसरशिप का यह स्तर सभी भारतीय नागरिकों (कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन) को गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के संवैधानिक जनादेश से बहुत दूर कर देता है।

आगे की राह:

- **संतुलित कानून की आवश्यकता:**
 - सेंसरशिप कानून अतिसंवेदनशील नहीं हो सकते हैं। उन्हें एक तरफ प्रसारण और सूचना प्रसार के उद्देश्य मानकों को बनाए रखने और दूसरी तरफ कला, अभिव्यक्ति, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति रचनात्मकता को बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को परभाषित करने की आवश्यकता:**
 - ऐसे स्पष्ट नियम होने चाहिए जिनके लिये अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये वास्तविक खतरे का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हो। यह आतंकवाद से संबंधित कानून के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ नई शक्तियों के मसौदे के दौरान अक्सर सीमित पारदर्शिता होती है।
- **स्व-वनियमन की आवश्यकता:**
 - एक खुले समाज में, सूचना नियंत्रण की कोई भी प्रणाली स्व-वनियमन की डिग्री पर निर्भर करेगी, भले ही राज्य द्वारा उसकी देखरेख की जाए। अतएव इस हेतु अन्य विकल्प अव्यावहारिक और वैचारिक रूप से अस्वीकार्य हैं।
- **सक्रिय दृष्टिकोण:**
 - अधिसूचना और प्रलेखन के संदर्भ में इन मामलों का संचालन सक्रिय होनी चाहिए।
 - जवाबदेही की वर्तमान प्रणाली तभी सम्भव है जब स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की इच्छाएँ लोकतांत्रिक समाज की ज़रूरतों के साथ समन्वय में हों, जिसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।